(b) The country is likely to become self-sufficient in rubber by the end of the 8th Plan. To achieve this, a three pronged strategy on the following lines has been suggested by the Rubber Board during the 8th plan.

(1) Expansion of area under rubber by 80,000 hectares.

(2) Replantation of old and low yielding areas with modern high yielding cultivars in an area of 40,000 hectares.

(3) Raising productivity of existing plantations by popularising adoption of modern technology in plant protection, manuring, harvesting and crop processing.

The proposal is pending finalisation of 8th Plan outlays.

Loss in Konark Jute Mill in Orissa

12. SHRI JAGADISH JANI; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Konark Jute Mill in Orissa is running at loss;

(b) if so, since when and what are the reasons therefor; and

(c) what steps have been taken to improve the performance of that mill.

THE MINISTER OF TEXTILES AND "" FOOD PROCESSING INDUSTRY (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV): (a) to (c) Information in respect of Konark Jute Mill Ltd., a Joint Secfor Undertaking of the Industrial Development Corporation of Orissa Ltd. and the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. is being collected and will be laid on the Table of the House.

Increasing export of handlooms and handicrafts from Orissa

13. SHRI JAGADISH JANI; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the names of the countries importing handlooms and handicrafts from Orissa;

(b) whether there is Scope for increasing the export of handlooms and handicrafts from that State; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government in that direction during 1990-91?

THE MINISTER OF TEXTILES AND FOOD PROCESSING INDUSTRY (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV): (a) State-wise export figures are not maintained. EEC and USA are main markets for export of handloom. and handicraft products from India.

(b) and (c) Government have been taking a number of Steps to boost exports of handlooms and handicrafts from the country, including Orissa, which include sending trade delegations, conducting market studies and market research, releasing advertisements in foreign trade magazines and distribution of publicity material, participation in fairs in major markets, quality improvement and grant of export incentives etc.

परिचालन में काला धन

14. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनुमानत: कुल कितना काला धन परिचालन में है ;

(ख) सरकार के मूल्यांकन के अनुसार किन-किन व्यवसायों में काले धन का निवेश किया गया है ;

(ग) काले धन का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) देश में काले धन के परिचालन की राशि के संबंध में कोई

सरकारी अनुमान नहीं है । राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने "आस्पेक्ट्स आ ब्लैक इकानामी इन इंडिया" नामक अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 के लिए काले धन की राशि का अनुमान 31,584 करोड़ रुपये से 36,786 करोड़ रु० के बीच लगाया है । तथापि, इस रिपोर्ट के लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि उनका अनुमान अनेक पूर्वानुमानों एवं अनुमानों पर आधारित है।

(ख) वे व्यवसाय अथवा क्षेत्र, जहां काला धन सृजित होता है अथवा उसका निवेश किया जाता है, स्थायी नाम नहीं रखते हैं । ये समय-समय पर बदलते रहते हैं । फिर भी, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने उन निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है, जहां काला धन सामान्यतः उत्पन्न होता है :

(1) स्थावर सम्पदा संबंधी लेन देन ;

(2) बड़े पैमाने पर विनिर्माण ;

(3) फिल्म उद्योग ;

(4) व्यवसाय ;

(5) निर्माण ; और

(6) तस्करी ।

(ग) मुद्रा-स्फीति पर काले धन के प्रभाव के बारे में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है । काले धन के पैदा होने से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे—मुद्रास्फीति बढ़ना एवं स्पष्ट उपभोग तथा साथ ही साथ कर पद्धति के औचित्य को भी दुर्बल बनाना।

(घ) सरकार कर अपवंचन को रोकने तथा काले धन का पता लगाने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक उपाय, जैसाकि वह ठीक समझती है, करती है । आयकर विभाग द्वारा किए गए कुछेक उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(1) सर्वेक्षण संबंधी सुव्यवस्थित कार्यवाइयां ;

(2) समुचित मामलों में तलाशी एवं अभिग्रहण कार्यवाहियां ;

(3) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना का सत्यापन करना ;

(4) चुनिन्दा मामलों में गहराई से जांच-पड़ताल करना ; और

(5) आयकर अधिनियम के अध्याय XX-ग के उपबंधों के अंतर्गत कतिपय अधिसूचित नगरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति का पूर्व क्रय अधिकार।

"फेरा" का उल्लंघन करने के लिए ओसवाल एग्रो इण्डस्ट्रीज के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना

15. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओसवाल एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को "फेरा" का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था । जैसा कि 5 दिसम्बर, 1990 के विभिन्न समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां, मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, लुधियाना के अध्यक्ष श्री अभय ओसवाल को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों का कथित उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने श्री अभय ओसवाल को दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को गिरफ्तार किया था। सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था तथा बाद में दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन्हें जमानत पर